ऊर्जा, सड़क और रेलवे को किराये पर देकर छह लाख करोड़ जुटाएगी सरकार

राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के तहत बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम का दावा

नई दिल्ली। ऊर्जा, सड़क और रेलवे के बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को छह लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना (एनएमपी) के तहत कुछ क्षेत्रों की संपत्तियों को ठेके पर देने का एलान किया। हालांकि, इनका स्वामित्व सरकार के पास बना रहेगा। वित्तमंत्री ने कहा, संपत्ति मुद्रीकरण में जमीन नहीं बेची जाएगी, बल्कि इस्तेमाल में नहीं आने वाली संपत्तियों का ही मुद्रीकरण होगा।

एनएमपी के तहत जिन सेक्टरों की पहचान की, उनमें सड़क, रेलवे और ऊर्जा क्षेत्र शामिल हैं। केंद्र की मुख्य संपत्तियों के मुद्रीकरण से चार वर्षों में यानी वित्त वर्ष 2022 से 2025 के दौरान छह लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। इसके बाद संपत्तियां अनिवार्यतः वापस करनी होगी। वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में स्थायी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए मुद्रीकरण की सतत प्रमुख साधन के रूप में पहचान की गई थी। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की तैयारी का बजट भी दिया गया था। नीति आयोग ने इंफ्रालाइन मंत्रालयों से परामर्श कर रिपोर्ट तैयार की है। वित्तमंत्री ने बजट भाषण में सार्वजनिक बुनियादी ढांचा संपत्ति का मुद्रीकरण अहम वित्तपोषण विकल्प बताया था। सरकार मुद्रीकरण को महज वित्तपोषण का साधन नहीं, बल्कि ढांचागत परियोजनाओं के रखरखाव व विस्तार की बेहतर रणनीति के तौर पर देख रही है। निजी निवेशक निश्चित राशि पर इसमें तय अवधि के लिए निवेश करेंगे और परिचालन-संवर्धन के बाद सरकार को संपत्ति लौटाएंगे। स्टेडियम व गोदाम लंबी अवधि के लिए लीज पर दिए जाएंगे। एजेंसी

>> सरकारी संपत्तियों में बढ़ेगा निजी निवेश : कारोबार

25 हवाई अड्डे और 400 रेलवे स्टेशनों में निजी निवेश

- चेन्नई, भोपाल, वाराणसी व वडोदरा सहित 25 हवाई अड्डों में निवेश
- 400 स्टेशनों, 90 पैसेंजर ट्रेनों, 741 किमी लंबी कोंकण रेलवे के लिए निवेश आमंत्रण

15 रेलवे स्टेडियमों और रेलवे कॉलोनियों में भी होगा निवेश।

चार वर्षों बाद सरकार को वापस करनी होगी संपत्ति

आय बढ़ाने के मकसद से सरकार गैस पाइपलाइन, सड़क, रेलवे स्टेशनों, गोदामों, स्टेडियमों को लीज पर देगी।
- अमिताभ कांत, मुख्य कार्यकारी, नीति आयोग

योजना का शुरुआत करतीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण

किस क्षेत्र से कितनी कमाई (करोड़ रुपये में)

नेहरू स्टेडियम, तीन अन्य साई स्टेडियम भी ठेके पर

सरकार ने इस योजना में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम व भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के तीन स्टेडियम भी भी रखे हैं। इनमें बंगलूरू व जीरकपुर के दो क्षेत्रीय केंद्र हैं।